

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 486—पीबीआर / 11

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-05-2015	<p>उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-12-2010 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :—</p> <p>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या</p> <p>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या</p> <p>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण</p> <p>आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं बतलाई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख परिलक्षित त्रुटि ही बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निकाले गये निष्कर्षों को अवैध ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।</p>	 <p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्ये उच्चालियर केम्प - भीषण

प्र०क्र०

फॅक्टु - 486 - PBR/2011

- क्रमांक १- घन्कयाम आ० भगवानदास पालीबाल, बयस्क
क्रमांक २- संजयकुमार आ० भगवानदास पालीबाल, बयस्क
उनिवासीगण- केतोधान जिला- रायतेन
हाल निवास- जे०जे०रोड बरेली जिला-रायतेन। मध्य।
द्वारा:- मुख्तार आम- सुनील पालीबाल आ०
भगवानदास
- क्रमांक ३- सुनील प्रश्नकुमार आ० भगवानदास पालीबाल
आयु-बयस्क निवासी-केतोधान जिला-रायतेन
हाल निवास - जे०जे० रोड बरेली ॥रायतेन॥
- - - आवेदकगण

--- विरुद्ध ---

- १- महेश आ० गोवर्धनदास, बयस्क
२- दिनेश आ० गोवर्धनदास, बयस्क
३- योगेश आ० गोवर्धनदास, बयस्क
४- श्रीमति साकित्रीबाई बिधवा त्व०गोवर्धनददत
तमस्त निवासीगण ग्राम-केतोधान तह०उदयपुरा
जिला- रायतेन।

---- अनावेदकगण

पुनः बिलोकन अन्तर्गत धारा-५। म०प्र०भ० रा० स० १९५९.

महोदय,

आवेदकगण द्वारा निगरानी प्र०क्र० १५६९/१/२००३ में पारित
आदेश दि० २१/१२/०१० से दुष्टि एवं असंष्टि होकर यह पुनः बिलोकन
माननीय न्यायालय के समर्थ प्रस्तुत है।